

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २२१]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल २८, १९७२/वैशाख ८, १८९४

No. 221]

NEW DELHI, FRIDAY APRIL 28, 1972/VAISAKHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1972.

**G.S.R. 263(E).**—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, namely:—

**1. (1)** These rules may be called the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) (Amendment) Rules, 1972.

**(2)** They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, after rule 6, the following rule shall be added, namely:—

**6A. Leave Travel Concession to visit home town.**—Notwithstanding anything contained in rule 6, a Judge of the Supreme Court shall be entitled to travel concession for himself and the members of his family for visiting his permanent residence in his home State during his leave, once in a block of two years, in accordance with rule 6 of the Supreme Court Judges Rules, 1959, read with rules applicable in this behalf to a member of the Indian Administrative Service holding the rank of Secretary to the Government of India. For this purpose 'leave' shall include vacation:

**Provided** that the Judge and his wife will have the option to travel by air subject to the condition that reimbursement of air fare will be per-

mitted after deducting the rail fares which he would have been liable to pay under the Leave Travel Concession applicable to a member of the Indian Administrative Service holding the rank of Secretary to Government of India."

[No. 1/7/72-Jus.]

P. P. NAYYAR, R. Secy.

## विधि तथा न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 263(अ).—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 में, नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"6क, सदन-गर्जना जाने-जाने के लिए छुट्टी की यात्रा-रियायत—नियम 6—में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने लिए या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए अपनी छुट्टी के दौरान अपने राज्य में अपने स्थायी निवास स्थान जाने-आने के लिए द्वि-वर्ष खण्ड में एक बार, इस निमित्त भारत सरकार के सचिव की पंक्ति धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को लागू नियमों के साथ संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 6 के अनुसार यात्रा-रियायत का हकदार होगा। इस प्रयोजन के लिए "छुट्टी" में प्रत्येक वर्ष की सम्मिलित छुट्टी होगी।

परन्तु न्यायाधीश तथा उनकी पत्नी, अपने विकल्प पर इस शर्त के अधीन रहते हुए, वायुयान द्वारा यात्रा करेंगे, कि वायुयान द्वारा यात्रा किराये की प्रतिपूर्ति उस रेल किराये की कटौती करके अनुभूत की जाएगी, जो भारत सरकार के सचिव की पंक्ति धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को लागू छुट्टी की यात्रा रियायत के अधीन उसे देना पड़ता।

[संख्या 1/7/72-न्याय-०]

प्रेम प्रसाद नय्यर, संपुक्त सचिव,